जैपसन इंटरनेशनल और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

भारतीय स्टेट बैंक और अन्य,-प्रतिवादी।

1987 का सिविल संशोधन संख्या 664, 12 अक्टूबर 1988।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V). order 39, नियम 1 और 2–विक्रेता साख पत्र के बदले माल की आपूर्ति कर रहा है–साख पत्र की पुष्टि नहीं की गई है।–विक्रेता अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर बातचीत के लिए दस्तावेजों का समर्थन कर रहा है–बैंक राशि को 'रिजर्व के तहत' जमा कर रहा है–प्रथम दृष्टया मामला- का अस्तित्व.

माना गया कि भुगतान विक्रेता के समर्थन के आधार पर वादी बैंक द्वारा 'रिजर्व के तहत' बातचीत किए गए दस्तावेजों के खिलाफ किया गया था कि दस्तावेजों पर क्षतिपूर्ति बांड द्वारा समर्थित जोखिम और जिम्मेदारी पर बातचीत की जानी चाहिए। प्रथम दृष्टया, मेरे विचार से ऐसी स्थिति में जब वादी बैंक रियाद बैंक से बातचीत किए गए दस्तावेजों की कार्यवाही का एहसास करने की स्थिति में नहीं है, तो वह विक्रेता के उपरोक्त वचन और क्षतिपूर्ति पर वापस आ सकता है और उसके द्वारा किए गए भुगतान को वापस ले सकता है। 'अंडर रिजर्व'. बैंकिंग ट्रांस में 'अंडर रिजर्व' भुगतान को समझा जाता है

कार्रवाई का मतलब यह है कि धन प्राप्त करने वाला इसे अपना नहीं मान सकता है, लेकिन मांगने पर इसे वापस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुविधा का संतुलन स्पष्ट रूप से सामान्य बैंकिंग लेनदेन को आगे बढ़ने की अनुमति देने में निहित है। (पैरा 14).

श्री हरि राम जिला न्यायाधीश, अंबाला की अदालत के दिनांक 30 अक्टूबर, 1986 के श्री जय की पुष्टि करने वाले आदेश के पुनरीक्षण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के तहत याचिका

भगवान शर्मा, अतिरिक्त वरिष्ठ उप न्यायाधीश, अम्बाला कैंट ने दिनांक 29 जनवरी, 1985 को अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की और प्रतिवादियों को एफ.डी.आर. पर बातचीत करने से रोक दिया गया। 27 सितंबर

1982 और 5 नवंबर 1983 के आवेदन में उल्लेख किया गया है और उन्हें उक्त खातों से कोई भी राशि निकालने से रोका गया है, और प्रतिवादियों को 28 अगस्त, 1985 को अपना लिखित बयान दर्ज करने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर उनका बचाव रद्द कर दिया जाएगा। . (जिला जज,

अम्बाला, - दिनांक 30 अक्टूबर, 1986 के आदेश द्वारा पक्षों को उनके वकील के माध्यम से 10 नवंबर, 1986 को विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया और विद्वान ट्रायल कोर्ट को मामले के शीघ्र निपटान के लिए प्रभावी कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया)।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एस. जैन और अधिवक्ता संजीव शर्मा उपस्थित थे।

आर.के. छिब्बर, अधिवक्ता, मोहन लाल गुप्ता, अधिवक्ता, के साथ

उत्तरदाताओं.

डी. एस. सहगल, जे.

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1989)1

प्रलय

यह निर्णय 1987 के सिविल पुनरीक्षण संख्या 663 और 664 का निपटान करेगा। ये दोनों पुनरीक्षण याचिकाएं विद्वान जिला न्यायाधीश-अंबाला द्वारा पारित 30 अक्टूबर, 1986 के सामान्य आदेश से उत्पन्न हुई हैं। दोनों मामलों के तथ्य समान हैं और इसमें शामिल कानून के बिंदु भी समान हैं। अतः इस निर्णय से दोनों याचिकाओं का एक साथ निस्तारण करना सुविधाजनक है। हालाँकि, पार्टियों और दस्तावेजों के अलावा तथ्यों का संदर्भ, जब तक कि अन्यथा * विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो, 1987 के नागरिक संशोधन संख्या 664 को जन्म देने वालों से किया जाएगा।

(2) मैसर्स जैपसन इंटरनेशनल, अंबाला, मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 1 (संक्षेप में 'विक्रेता') मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 2 से 5 के रूप में शामिल किए गए चार साझेदारों से बना है। उन्होंने रियाद हाउस प्रतिष्ठान, रियाद, सऊदी अरब (संक्षेप में 'खरीदारों') के साथ वैज्ञानिक वस्तुओं के निर्यात के माध्यम से बिक्री के लिए एक अनुबंध में प्रवेश किया। खरीदारों ने विक्रेता के पक्ष में नेशनल कमर्शियल बैंक, रियाद (संक्षेप में 'रियाद बैंक') के माध्यम से 6 अगस्त, 1980 को एक ऋण पत्र खोला। इसे बॉम्बे स्थित भारतीय स्टेट बैंक की विदेशी शाखा (संक्षेप में 'वादी बैंक') को भेजा गया था। वादी बैंक की उक्त शाखा ने विक्रेता को आगे के ट्रांस मिशन के लिए माल रोड, अंबाला कैंट स्थित अपनी शाखा को क्रेडिट पत्र भेजा, जो क्रेडिट पत्र के तहत लाभार्थी था। विक्रेता ने 5 सितंबर, 1980 को वादी] बैंक की अंबाला कैंट स्थित अपनी उपरोक्त शाखा में एक चालू खाता खोला। इसने माल की अपनी पहली खेप भेजी, चालान दिनांक के अनुसार।

12 अक्टूबर, 1980 और 31 अक्टूबर, 1980 का लदान बिल सी.आई.एफ. का प्रतिनिधित्व करता है। रुपये का मूल्य 1,63,864.20 और विनिमय का एक बिल निकाला जिसे वादी बैंक ने भारतीय डिमांड ड्राफ्ट संख्या 7/109 के रूप में माना। जब इन दस्तावेजों को विक्रेता द्वारा उनसे बातचीत करने और आय को उसके चालू खाते में जमा करने के अनुरोध पत्र के साथ सौंपा गया, तो वादी बैंक ने विक्रेता को सूचित किया कि बैंक को सौंपे गए दस्तावेजों में विभिन्न विसंगतियां थीं। उनका विवरण साख पत्र में दिए गए विवरणों के अनुरूप नहीं था।

(3) इसके बाद विक्रेता ने 13 नवंबर, 1980 को बातचीत के लिए अपने लेटर ऑफ अनुरोध पर निम्नलिखित का समर्थन किया-;

प्रभाव :

"कृपया साख पत्र की शर्तों के अनुसार और उसमें किसी भी विसंगति के मामले में हमारे जोखिम और जिम्मेदारी पर दस्तावेजों पर बातचीत करें।

उपरोक्त पत्र पर विक्रेता के भागीदार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। वादी बैंक ने 15 तारीख को दस्तावेजों पर बातचीत की। नवंबर, 1980 और रुपये की राशि जमा की गई। 1,63,864.29 से

विक्रेता का चालू खाता. हालाँकि, दस्तावेज़ों पर विक्रेता की लागत और जिम्मेदारी पर वादी बैंक द्वारा "आरक्षित के तहत" बातचीत की गई थी। कुछ बैंक शुल्क भी विक्रेता के खाते से डेबिट किए गए थे। 13 नवंबर, 1980 के पत्र पर अपने उपरोक्त समर्थन का समर्थन करने के लिए विक्रेता ने वादी के पक्ष में 9 जनवरी, 1981 को एक क्षतिपूर्ति बांड भी निष्पादित किया।

रुपये के लिए बैंक. 1,63,864.29.

(4) इसके बाद विक्रेता ने दूसरी खेप भेजी, - चालान दिनांक 22 नवंबर, 1980 के माध्यम से। दस्तावेज़ इसी तरह वादी बैंक के पास जमा किए गए थे; पहली खेप के मामले में विसंगतियों को एक बार फिर से उजागर किया गया; दस्तावेज़ में लाभार्थी के जोखिम और जिम्मेदारी पर उनके निष्पादन क्षतिपूर्ति बांड पर भी बातचीत की गई थी। इसके बाद, विक्रेता द्वारा तीसरी और चौथी खेप भेजी गई, क्रमशः 15 दिसंबर, 1980 और 22 दिसंबर, 1980 के चालान के माध्यम से, जिसे वादी बैंक के पास जमा किया गया था और विक्रेता की लागत और जोखिम पर "रिजर्व के तहत" बातचीत की गई थी। .

(5) जब खेप रियाद, सऊदी अरब पहुंची, तो खरीदार ने विसंगतियों के कारण माल की डिलीवरी लेने और दस्तावेज़ का सम्मान करने से इनकार कर दिया। यह आरोप लगाया गया था कि विवरण माल की गुणवत्ता साख पत्र में दी गई जानकारी के अनुरूप नहीं थी। वादी बैंक ने तदनुसार विक्रेता को सूचित किया और वादी बैंक द्वारा किए गए आकस्मिक दंत शुल्क के साथ बिलों की पूरी राशि जमा करने का अनुरोध किया, लेकिन विक्रेता ऐसा करने में विफल रहा। विक्रेता को कानूनी नोटिस देने के बाद वादी बैंक ने रुपये की वसूली के लिए तत्काल मुकदमा दायर किया। 19.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 7,22,049.75

रु.

(6) मुकदमे की स्थापना के साथ ही 27 सितंबर, 1982 को वादी बैंक द्वारा आदेश 38 नियम 5 के साथ पठित आदेश 39 नियम 1 और 2 नागरिक संहिता के तहत एक आवेदन दायर किया गया था।

प्रक्रिया (संक्षेप में 'संहिता') - वादी बैंक ने आरोप लगाया कि विक्रेता और उसके साझेदार डिक्री के निष्पादन में देरी करने और उसे विफल करने के उद्देश्य से अपनी संपत्तियों को छुपाने और उन्हें अंबाला में सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जो अंततः उनके विरुद्ध पारित किया जा सकता है। संपत्तियों, मशीनरी और सावधि जमा रसीदों (एफ.डी.आर.) का विवरण इसमें दिया गया था

यह आरोप लगाया गया था कि विक्रेता और उसके साझेदार वादी बैंक को भुगतान से बचने के उद्देश्य से इसे निपटाने की कोशिश कर रहे थे। यह रेखांकित किया गया था कि सूट एमक्वांट काफी भारी है और यदि प्रतिवादी चल संपत्ति का निपटान करने में सक्षम थे और अचल संपत्ति, वादी बैंक डिक्री निष्पादित करने में सक्षम नहीं होगा। प्रार्थना की गई कि विक्रेता और उसके साझेदारों की उसमें उल्लिखित चल और अचल संपत्ति को निर्णय से पहले कुर्क किया जाना चाहिए या उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस आवेदन का नोटिस प्रतिवादियों को दिया गया जिन्होंने इसमें शामिल आरोपों का खंडन करते हुए अपना जवाब दाखिल किया।

(7) इस बीच वादी बैंक ने संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के साथ पठित आदेश 38 नियम 5 के तहत 5 नवंबर 1983 को एक और आवेदन किया। उसमें यह बताया गया था मेसर्स जम्बू पार्षद एंड संस एक साझेदारी फर्म है। इसके भागीदार सर्वश्री ज्ञानचंद जैन हैं। नेम चंद जैन, अनिल जैन और ललित जैन। एफ.डी.आर. का विवरण इसके चालू खाते के अलावा फर्म भी दी गई। यह कहा गया कि श्री ज्ञान चंद जैन मुकदमे में प्रतिवादियों में से एक हैं। अनिल जैन सहयोगी कंपनी मेसर्स यूनियन साइंटिफिक का भागीदार है जिसके खिलाफ वसूली के लिए एक समान मुकदमा दायर किया गया था और उसे उस मुकदमे में प्रतिवादी नंबर 2 के रूप में शामिल किया गया था। उस मुकदमे में उधारकर्ता होने के नाते श्री ज्ञान चंद जैन को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में शामिल किया गया था। यह कहा गया था कि जहां तत्काल मुकदमा

सात लाख रुपये से अधिक की वसूली के लिए है, वहीं दूसरा केवल दस लाख रुपये से अधिक की वसूली के लिए है। आगे उल्लेख किया गया है कि जैपसन इंटरनेशनल (विक्रेता) मेसर्स यूनियन साइंटिफिक (दूसरे मुकदमे में प्रतिवादी) और मेसर्स जम्बू पार्षद एंड संस एक के स्वामित्व वाली सहयोगी संस्थाएं हैं। परिवार जहां या तो बेटे, उनकी पत्नियां या प्रतिवादी क्रमांक 2 से 5 स्वयं भागीदार थे। यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी मेसर्स जम्बू प्रसाद एंड संस के नाम पर राशि निकालने की कोशिश कर रहे थे। वे एफ.डी.आर. को भुनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यह प्रार्थना भी की गई कि एफ.डी.आर. और इन फर्मों के बैंक खाते भी कुर्क किए जाने चाहिए या इस बीच बचाव पक्ष को एफ.डी.आर. वापस लेने से रोका जाना चाहिए। और चालू खातों में पड़ी राशि। इस आवेदन का जवाब भी प्रतिवादियों द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने तर्क दिया था कि मेसर्स जम्बू पार्षद एंड संस एक स्वतंत्र फर्म है जिसकी एक अलग कानूनी इकाई है। इसकी संपत्ति को न तो कुर्क किया जा सकता है और न ही इसे प्रतिबंध का विषय बनाया जा सकता है। आवेदन का इस आधार पर भी विरोध किया गया था कि वादी बैंक के पास योग्यता के आधार पर कोई भी मामला नहीं था और दायर किए गए मुकदमे धोखाधड़ी वाले थे।

(8) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने मूल रूप से फैसले से पहले उचित प्रयासों की कुर्की के लिए इन दो आवेदनों में की गई प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसका आदेश अपील का विषय बन गया जब इसे उलट दिया गया और मामले को नए फैसले के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया। वादी बैंक ने इस न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जिसमें निर्देश दिया गया कि संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत उसकी प्रार्थना पर विचार किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस अंतराल में वादी बैंक ने 16 अप्रैल, 1985 को एक और आवेदन किया।

संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत आवेदन में संशोधन हेतु। उसमें कहा गया था कि आवेदन के पैरा 11 में कुछ लिपिकीय गलतियाँ हो गई हैं जिन्हें सुधारा जाना चाहिए और फिर आवेदन का निपटारा किया जाना चाहिए।

(9) वादी बैंक द्वारा दायर किए गए सभी आवेदनों पर अंततः विद्वान अतिरिक्त वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, अंबाला द्वारा निर्णय लिया गया। - उनके आदेश दिनांक 29 जुलाई, 1985 द्वारा। उन्होंने माना कि वादी बैंक एक प्राइमा बनाने में सक्षम है प्रथम दृष्टया मामला इसके पक्ष में है और सुविधा का संतुलन विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करने में निहित है। इसलिए, इसने उन्हें एफ.डी.आर. पर बातचीत करने से रोक दिया। और 27 सितंबर के आवेदनों में उल्लिखित खातों से कोई भी राशि निकालने से। 1982 और 5 नवंबर. 1983. यह देखा गया कि यदि एफ.डी.आर. तो प्रतिवादियों को कोई अपूरणीय क्षति नहीं होगी। बैंक की अभिरक्षा में रखे गए थे क्योंकि उसी की राशि पर ब्याज मिलेगा और यदि वादी बैंक मुकदमे में सफल नहीं हुआ, तो मूल राशि और ब्याज भी प्रतिवादियों को भुगतान किया जाएगा। हालाँकि, इसने बचाव पक्ष को उनकी अचल संपत्तियों को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए वादी बैंक की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। यह देखा गया कि यह उचित होगा कि अचल संपत्ति को विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के दायरे से बाहर रखा जाए क्योंकि अचल संपत्तियों के खिलाफ किसी भी प्रतिबंध का निर्देश होगा।

प्रतिवादियों की व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा डालना

10) वादी बैंक, विक्रेता, फर्म और उसके साझेदारों के अलावा मेसर्स जम्बू पार्षद एंड संस के साझेदार, जो बिना किसी संदेह के विक्रेता के साझेदारों के परिवार के सदस्य हैं, ने विद्वान ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी-अपनी अपीलें दायर कीं। दिनांक 9 जुलाई. 1985. विस्तृत चर्चा के बाद दोनों प्रतिद्वंदी पक्षों की अपीलें विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गईं, -

30 अक्टूबर के अपने फैसले के तहत। 1986, इस प्रकार याचिकाकर्ता जो विक्रेता हैं और श्री जम्बू पार्षद जैन के पुत्र श्री ज्ञान चंद जैन, जो इसके एक भागीदार हैं, ने इस न्यायालय में तत्काल पुनरीक्षण याचिका दायर की है। यह देखा जा सकता है कि वादी बैंक ने क्रॉस- दायर किया था। आपत्तियाँ संख्या 6-1987 की सीआईआई लेकिन उन्हें एस.पी. गोयल, जे. द्वारा 13 मई 1987 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह माना गया था कि पुनरीक्षण याचिका में कोई भी प्रति-आपत्ति सक्षम नहीं है।

अंतरिम आदेश के ख़िलाफ़

(11) दोनों न्यायालयों द्वारा एक समवर्ती खोज रिकॉर्ड होना: नीचे वादी बैंक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन उसके साथ है और विक्रेता और उसके भागीदारों को कोई अपूरणीय चोट नहीं होगी विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुदान से, सामान्य प्रक्रिया में, संहिता की धारा 115 के तहत नीचे के न्यायालयों के आदेशों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। चूँकि, हालाँकि, पार्टियों के विद्वान वकील ने मेरे समक्ष इस विचार के पक्ष और विपक्ष में विस्तृत दलीलें दीं कि वादी बैंक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है, अगर मैं इस पर चर्चा नहीं करता हूँ, तो यह उनके लिए अनुचित होगा। संक्षिप्त। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मेरे द्वारा किया गया कोई भी अवलोकन वादी बैंक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होने के प्रश्न तक ही सीमित है और अंतिम के दौरान विक्रेता के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(12) विक्रेता के विद्वान वकील ने विभिन्न दस्तावेजों के संदर्भ में बताया कि खरीदार रियाद के कहने पर। बैंक ने वादी बैंक की बॉम्बे स्थित विदेशी शाखा से इसकी पुष्टि करने के अनुरोध के साथ विक्रेता के पक्ष में ऋण पत्र खोला। उन्होंने मेरा ध्यान साख पत्र की एक प्रति की ओर आकर्षित किया जिसमें इस आशय की उभरी हुई मोहरें हैं कि इसकी पुष्टि वादी बैंक की उक्त बॉम्बे शाखा द्वारा की गई है। उनका कहना है कि तभी साख पत्र इसकी माल रोड, अंबाला कैंट स्थित शाखा को भेजा गया था और इस प्रकार विक्रेता को प्रेषित किया गया था। उन्होंने मेसर्स तारापोर एंड कंपनी मद्रास बनाम मेसर्स वी/ओ ट्रैक्टर ईओपोर्ट मॉस्को और अन्य पर दृढ़ता से भरोसा किया, (1) और तर्क दिया कि एक पुष्टिकृत ऋण पत्र खोलना एक सौदा है:

बैंकर और माल के विक्रेता के बीच, जो बैंकर पर भुगतान करने का पूर्ण दायित्व लगाता है, भले ही माल के संबंध में पार्टियों के बीच कोई विवाद हो।

अनुबंध पर हैं या नहीं। एक पक्का साख पत्र देकर सामान बेचने वाला विक्रेता इस आश्वासन के तहत सामान बेच रहा है कि उसे कीमत प्राप्त करने से कोई नहीं रोकेगा। यदि खरीदार के पास लागू करने योग्य दावा है कि समायोजन रिफंड के माध्यम से किया जाना चाहिए? विक्रेता द्वारा न कि क्रेता द्वारा प्रतिधारण के माध्यम से। साख पत्र किसी अयोग्य लेनदेन से स्वतंत्र है। अपरिवर्तनीय साख पत्र की स्वायत्तता सुरक्षा का हकदार है।

(13) इस प्रस्ताव पर शायद ही कोई विवाद हो। हालाँकि, वादी बैंक का मामला यह है कि साख पत्र भेजा गया था

रियाद बैंक द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई। इसके वकील ने मेरा ध्यान विदेशी मुद्रा कारोबार की मात्रा पर इसके निर्देशों की ओर आकर्षित किया।'

वी, अनुच्छेद 34 और प्रस्तुत किया गया कि क्रेडिट पत्र की पुष्टि के प्रयोजन के लिए कमीशन का भुगतान या तो प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना है।

बैंक या लाभार्थी (इस मामले में विक्रेता) द्वारा निर्दिष्ट दर पर। ऐसे मामले में जहां लाभार्थी से वृद्धि पुष्टिकरण कमीशन एकत्र किया जाना है, सलाह देने वाली शाखा को प्रासंगिक अग्रेषण पत्र में निम्नलिखित पैराग्राफ को शामिल करना है और कमीशन के प्रेषण के बाद ही बैंक की पुष्टि करनी है जो निम्नलिखित शब्दों में होनी चाहिए :–

“हमें शुरुआती बैंक से हमारे भुगतान के विरुद्ध इस क्रेडिट पर अपनी पुष्टि डालने के निर्देश प्राप्त हुए हैं आपके द्वारा कमीशन. हम आपके विप्रेषण की प्राप्ति पर अपनी पुष्टि जोड़ने के अपने विकल्प के लिए तैयार हैं...

उन्होंने अनुच्छेद 35 की ओर भी मेरा ध्यान आकर्षित किया जो मूल पत्र के ऊपर पुष्टिकरण के शब्दों को निर्धारित करता है जिस पर शाखा प्रबंधक/:' एक प्रभाग के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं और यह निम्नलिखित शब्दों में है: –

“यह श्रेय हमारी पुष्टि को दर्शाता है।

एसडी/-

भारतीय स्टेट बैंक के लिए, शाखा प्रबंधक।"

उनका कहना है कि 6 अगस्त, 1980 के ऋण पत्र पर जो कुछ अंकित है, वह उपरोक्त आवश्यकता का उत्तर नहीं देता है और इस प्रकार इसे ऋण के पुष्ट पत्र के रूप में नहीं माना जा सकता है और वास्तव में माल रोड, अंबाला द्वारा भी ऐसा नहीं किया गया है। वादी बैंक की कैंट शाखा या विक्रेता द्वारा। मेरे अनुसार यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि जब विक्रेता द्वारा वादी बैंक के माध्यम से चार चालानों और लदान बिलों में से प्रत्येक पर बातचीत करने की मांग की गई तो उसने सामान के विवरण में मौजूद विसंगतियों की ओर इशारा किया जैसा कि उल्लेख किया गया है। साख पत्र में दिए गए दस्तावेज़ों की तुलना में दस्तावेज़। इस स्थिति का एहसास होने पर ही विक्रेता ने हर बार इस आशय का समर्थन किया कि दस्तावेजों पर किसी भी विसंगति के मामले में अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर बातचीत की जानी चाहिए और आगे क्षतिपूर्ति बांड द्वारा इसका समर्थन किया गया। फिर भी भुगतान किया गया या राशि वादी बैंक द्वारा विक्रेता के चालू खाते में "रिजर्व के तहत" और विक्रेता की लागत और जोखिम पर जमा की गई। इस प्रकार उनका मानना है कि उपरोक्त साख पत्र कोई पुष्ट विभाज्य अपरिवर्तनीय साख पत्र नहीं था। जब खरीदार और रियाद बैंक द्वारा दस्तावेज़ों का अनादर किया गया था, तो वादी बैंक को क्षतिपूर्ति पत्र लागू करने और विक्रेता को बैंक के भुगतान को "रिजर्व के तहत" वापस लेने का पूरा अधिकार था।

(14) इस प्रश्न पर कि साख पत्र एक निश्चित साख पत्र है या नहीं, दोनों पक्षों में तीखी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, मैं इस प्रश्न पर कोई निश्चित निष्कर्ष देना न तो समीचीन मानता हूं और न ही उचित। हालाँकि, देखने वाली बात यह है कि भुगतान विक्रेता के समर्थन के आधार पर वादी बैंक द्वारा 'रिजर्व के तहत' बातचीत के दस्तावेजों के खिलाफ किया गया था कि दस्तावेजों पर उसके जोखिम और जिम्मेदारी पर क्षतिपूर्ति के साथ बातचीत की जानी चाहिए। गहरा संबंध। प्रथम दृष्टया, मेरे विचार से, ऐसी स्थिति में जब वादी बैंक रियाद बैंक से बातचीत किए गए दस्तावेजों की कार्यवाही का एहसास करने की स्थिति में

नहीं है, तो वह विक्रेता के उपरोक्त वचन और क्षतिपूर्ति पर वापस आ सकता है और किए गए भुगतान को वापस ले सकता है। यह "अंडर रिजर्व" है। मुझे इस दृष्टिकोण के लिए यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बनाम बैंक ऑफ इंडिया और से समर्थन मिलता है

अन्य, (2). बैंकिंग लेनदेन में "रिजर्व के तहत" भुगतान का अर्थ यह समझा जाता है कि धन प्राप्तकर्ता इसे अपना नहीं मान सकता है, लेकिन मांग पर इसे वापस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुविधा का संतुलन स्पष्ट रूप से सामान्य बैंकिंग की अनुमति देने में निहित है

लेन-देन आगे बढ़ना है।

15) अन्यथा यहां भी विवाद विक्रेता और बैंकर के बीच है। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक्स के मामले (सुप्रा) में यह माना गया है कि क्रेडिट के एक पुष्टिकृत पत्र को खोलना बैंकरों और सामान के विक्रेता * के बीच एक सौदेबाजी है जो ओह रैंकर को भुगतान करने का पूर्ण दायित्व लगाता है। हालाँकि, बैंकर विक्रेता द्वारा निकाले गए विनिमय के बिलों का सम्मान करने के लिए बाध्य या हकदार नहीं है, जब तक कि वे और उनके साथ आवश्यक दस्तावेज, बिल्कुल अनुपालन में न हों।

क्रेडिट की शर्तें. ऐसे दस्तावेज़ों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

(16) इस स्तर पर यह कहना कि वादी बैंक के पास प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है और उसे एफ.डी.आर. को सुरक्षा के रूप में अपने पास रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। और विक्रेता के बैंक खातों में शेष राशि और अनुमति देने के लिए

कहा गया है कि यह राशि उसके हाथ से निकल जाने से बैंक को बड़ा नुकसान होगा। यह सर्वविदित है कि बैंक जब व्यवसाय करते हैं तो वे केवल उस पैसे का लेन-देन करते हैं जो विभिन्न पक्षों से संबंधित होता है। बैंक केवल लेनदेन किए गए व्यवसाय के लिए कमीशन लेते हैं। जब वादी विक्रेता को "अंडर रिजर्व" भुगतान करके राशि से अलग हो जाता है और उसे खरीदार से बदले में भुगतान नहीं मिलता है तो उसे

विक्रेता से राशि वापस लेने या अपनी प्रतिभूतियों और शेष राशि को रखने की अनुमति दी जानी चाहिए जो उसकी संतुष्टि को पूरा कर सके। विक्रेता के विरुद्ध दावा.

(17) बैंकों और उनके ग्राहकों को आम तौर पर स्थापित बैंकिंग प्रणाली के तहत अपने संबंधित दायित्वों को लागू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। केवल असाधारण मामलों में ही न्यायालय को उनके द्वारा ग्रहण किए गए पारस्परिक दायित्वों की मशीनरी में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्हें न्यायालयों के हस्तक्षेप से मुक्त होकर सम्मानित होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(18) उपरोक्त चर्चा के आलोक में नीचे के न्यायालयों से सहमत होने पर कि सादे टिफ बैंक के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है, मुझे इन संशोधन याचिकाओं में कोई ताकत नहीं दिखती है जिन्हें खारिज कर दिया गया है। हालाँकि, मैं पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ता हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा